पाँचवा-स्तम्भ

CUTS International

हमारा मुख-पत्र

वर्ष 21, अंक 3/2020

कोरोना महामारी के बावजूद सतत् विकास के लक्ष्य हासिल करने के मिलेंगे अवसर - विशेषज्ञ

कोरोना महामारी के कारण सतत् विकास के अधिकांश लक्ष्यों को प्राप्त करने में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, हालांकि विशेषज्ञों को इसमें भी अवसर दिखाई दे रहे हैं। महामारी बहुत सी योजनाओं का निर्माण करने का अवसर प्रदान करती है, जो कि वर्तमान परिदृश्य को बदल देगी तथा सतत् खपत और उत्पादन के पेटर्न को अधिक मजबूती प्रदान करेगी।

उक्त विचार विशेषज्ञों ने 'कट्स' द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में व्यक्त किए। वेबिनार में अर्चना दत्ता, परियोजना समन्वयक, स्विच एशिया ने कहा कि भारत में विभिन्न राज्य सतत् उपभोग और उत्पादन की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जो कि सतत् विकास लक्ष्यों के उद्देश्य -12 को इंगित करते हैं। हालांकि कोरोना महामारी के चलते इस दिशा में किए गए प्रयासों में कुछ अड़चन भी आई है। उन्होंने कहा कि सतत् विकास के लक्ष्यों को पूर्ण करने की जिम्मेदारी सरकार के साथ-साथ अन्य भागीदारों व नागरिकों की भी है।

वेबिनार के प्रारम्भिक उद्बोधन में 'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी हितधारकों के द्वारा जब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किए जाएंगे, तब तक सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। हम देखते हैं कि सतत् विकास लक्ष्य-12 और 13 को प्राप्त करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। हालांकि कोरोना महामारी ने सतत् विकास लक्ष्य-12 से जुड़े क्षेत्रों में तत्कालिक रूप से कुछ राहत प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर कार्बनडाई ऑक्साइड उत्सर्जन में 17 फीसदी की कमी आई है। वैश्विक ऊर्जा की मांग में भी काफी कमी आई है। भारत में ऊर्जा खपत में 30 फीसदी की कमी देखी गई है। वायु प्रदूषण में भी काफी कमी दर्ज की गई है। हालांकि इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। प्लास्टिक की खपत, डिस्पोजल मास्क के उपयोग व ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था से इलेक्ट्रोनिक गैजेट्स का उपभोग अप्रत्याशित रूप से बढ़ा है, जिसका सतत् विकास लक्ष्य-12 से जुड़े क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

वेबिनार में ईवा आइडरस्ट्रोम, निदेशक, इकोलेबलिंग और ग्रीन कंजम्प्शन विभाग, स्वीडिश सोसायटी फॉर नेचर कंजरवेशन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पूरे समाज के उपभोग व उत्पादन पैटर्न में बदलाव का प्रमाण है। सर्कूलर इकोनोमी को अभी भी विकसित और संस्थागत बनाने की जरूरत है। संसाधनों के उपभोग में कमी लाना और पुनर्चक्रन को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि सतत् विकास लक्ष्य-12 हम सभी के अस्तित्व की एक धूरी है और हमें उसी के अनुसार अपनी व्यवस्था को आकार देना होगा।

केरल के पर्यावरण विभाग की प्रमुख शासन सचिव डॉ.ऊषा टाइटस ने स्वीकार किया कि समग्र सतत् विकास लक्ष्यों की रैंकिंग में केरल राज्य शीर्ष पर है। लेकिन सतत् विकास लक्ष्य-12 से जुड़े क्षेत्रों में निश्चित रूप से अपेक्षित विकास नहीं हुआ है। उन्होंने केरल में संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी और कहा कि आंकड़ों के संग्रहण में कई बार विभागों के बीच तालमेल की कमी के चलते सही स्थिति साफ नहीं हो पाती।

केरल इन्स्टीट्यूट ऑफ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के महानिदेशक डॉ. जॉय एलामन ने सतत् विकास लक्ष्य-12 एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्थानीय सरकारों को सशक्त एवं विभिन्न विभागों को एकीकृत करने पर बल दिया। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन के संबंध में विकेंद्रीकृत प्रबंधन सबसे अच्छा काम करता है।

कार्यक्रम में 12 देशों एवं भारत के 23 से अधिक राज्यों के 100 से ज्यादा प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

इस अंक में...

- मजाक बना दलबदल विरोधी कानून 3
- सतत् विकास लक्ष्यों की योजना 6
- दस में से एक व्यक्ति है बेरोजगार 7
- सबसे महंगी हमारी बिजली 8
- कैसे होगी पढ़ाई के नुकसान की भरपाई ? ... 10

भारत को ट्रांसफैट मुक्त बनाने के लिए संबंधित सभी अधिनियमों को तुरंत पास करना होगा- 'कट्स' इंटरनेशनल

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ), रिसोल्व टू सेव लाईफ एवं वाइटल स्ट्राटेजीज के संयुक्त तत्वावधान में ग्लोबल ट्रांस लिमिनेशन रिपोर्ट 2020 के द्वितीय संस्करण का एक उच्च स्तरीय ऑनलाइन कार्यक्रम में विमोचन किया गया।

यह रिपोर्ट विभिन्न स्तरों पर ट्रांसफैट के उन्मूलन हेतु यथा, अन्तरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय स्तर एवं सभी देशों द्वारा किए जा रहे प्रयासों, परिस्थितियों, चुनौतियों, अवसरों व विगत वर्ष की प्रगति के बारे में विस्तार से प्रकाश डालती है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 15 देशों ने, जिसमें विश्व की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या निवास करती है, 2017 से ट्रांसफैट उन्मूलन हेतु विशेष प्रयास किए हैं।

उनमें कनाडा व अमेरिका प्रमुख हैं। इन देशों ने सभी तेलों, वसाओं व खाने की वस्तुओं में ट्रांसफैट की करीब 2 प्रतिशत मात्रा निश्चित कर दी है और अन्य अधिनियम भी पास किए हैं। मगर, भारत व इसके पड़ोसी देशों में संबंधित अधिनियमों को पास करने तथा इस हेतु प्रभावी जांच व निरीक्षण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है। यद्यपि खाद्य सुरक्षा व मानक अधिकरण, भारत सरकार ने दिसंबर 2018 में ही सभी तेलों, वसाओं व खाने की वस्तुओं में 2 प्रतिशत ट्रांसफैट की मात्रा सुनिश्चित करने के अधिनियम तथा ट्रांसफैट को भारत में 2022 तक उन्मूलन करने पर कार्य कर रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इन प्रयासों की सराहना भी की है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के महा- निदेशक डॉ. टेड्रोस अद्यानोम धेब्रेयसस, ने रिपोर्ट का विमोचन करते हुए कहा कि कोरोना महामारी में हमें प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य की सुरक्षा हेत प्रयास करने होंगे। उन्होंने प्रत्येक राष्ट्र से अनुरोध किया कि 2023 तक सम्पूर्ण विश्व को ट्रांसफैट मुक्त बनाने के लक्ष्य की प्राप्ति में देर नहीं करनी चाहिए।

इस अवसर पर डॉ. ईराम राव, सहायक प्राध्यापक, दिल्ली विश्वविद्यालय ने कहा कि वैज्ञानिक साक्ष्यों के अनुसार हमारे खाने में आए प्रत्येक 2 ग्राम ट्रांसफैट से 23 प्रतिशत तक हृदय रोगों को बढ़ावा मिलता है। भारत में बच्चे बहुतायत से तली हुई चीजे खाने से ट्रांसफैट का अत्यधिक मात्रा में सेवन कर रहे हैं।

'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने कहा कि इस कोरोना महामारी में ट्रांसफैट मुक्त भोजन का महत्व बढ़ गया है। जिन लोगों में हृदय व मधुमेह की बीमारी है, उनमें कोरोना संक्रमण की ज्यादा आशंका होती है। उन्होंने एफएसएसएआई से ट्रांसफैट से संबंधित सभी अधिनियम तुरंत पास करने का अनुरोध किया, जिससे कि 2022 तक भारत में ट्रांसफैट उन्मूलन हो सके।

'कट्स' अनुसंधान के अनुसार सभी राज्य सरकारों को भी ट्रांसफैट उन्मूलन हेतु विशेष प्रयास करने चाहिए। उन्हें खाद्य सुरक्षा एवं जांच हेतु सुविधाएं विकसित करनी होगी साथ ही निगरानी व्यवस्था को सख्त करना होगा।

'कट्स' ने शुरू किया कोरोना पर जागरूकता अभियान

'कट्स' द्वारा राजस्थान के 11 जिलों (जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा, कोटा, झालावाड़ एवं जोधपुर) में कोरोना महामारी के खिलाफ विभिन्न जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया ।

'कट्स' के निदेशक जॉर्ज चेरियन ने बताया कि इन गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सामाजिक सुरक्षा, स्वच्छता, मास्क पहनने, शारीरिक दूरी रखने और सुरक्षित खाद्य के प्रति जागरूक करना है। ग्रामीणों को सतर्कता बरतने, सभी स्वास्थ्य प्रोटोकाल का पालन करने और संक्रमण से बचाव की जानकारी दी गई। ताकि वे इस महामारी से खुद को व अपने परिवार को बचा सकें।

जागरूकता गतिविधियों का शुभारंभ 1 जुलाई 2020 को चित्तौड़गढ़ के एराल गांव में किया गया। इसमें सम्बन्धित पोस्टर एवं संदर्भ सामग्री का विमोचन अतिरिक्त जिला कलेक्टर मुकेश कलाल एवं अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सरिता सिंह द्वारा किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, ए.एन.एम, आशा कार्यकर्ता, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, सामुदायिक लीडर एवं 'कट्स' के स्टाफ सदस्य उपस्थित थे।

सम्पन्न ने उठा लिया गरीबों का हक

कोरोना महामारी में सरकार द्वारा असहाय परिवारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 2500 रुपए और खाद्य सामग्री को सम्पन्न परिवारों द्वारा उठाए जाने का मामला सामने आया है। मामला जयपुर जिले की आमेर तहसील के पूनाना ग्राम पंचायत का है।

जांच में सामने आया कि ग्राम पंचायत में जिन 57 लोगों को आर्थिक सहायता दी गई उनमें से लाभ लेने योग्य मात्र 10 लोग ही हैं। बाकी 47 लोग सम्पन्न परिवारों से हैं, जिनके पास पक्के मकान और चौपहिया वाहन हैं। यह लोग आर्थिक सहायता व खाद्य सामग्री लेने के पात्र नहीं थे। यह एक ग्राम पंचायत का उदाहरण नहीं है, बड़े स्तर पर जांच हो तो प्रदेश में ऐसे अनगिनत मामले सामने आ सकते हैं। *(दै.भा., 04.08.20)*

अफसर चलाते रहे जनसुविधा पर कैंची

राजस्थान मेडिकल यूनिवर्सिटी (आरयूएचएस) का अस्पताल 11 साल में भी पूरा नहीं हो सका। बारां में नर्सिंग स्कूल का भवन 9 साल में भी नहीं बना। बच्चों की मौत के कारण सुर्खियों में आया कोटा मेडिकल कॉलेज ने यूआइटी के ठेकेदार पर 23 करोड़ रुपए की दरियादिली दिखा दी। जेंडर आधारित एक योजना में तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया। परिवहन विभाग कई हजार वाहनों से कर ही नहीं वसूल सका।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा राज्य विधानसभा में पेश चार रिपोर्टों से ऐसे कई खुलासे सामने आए हैं। इससे जाहिर होता है कि योजनाएं बनती है लेकिन सरकारी धन के दुरुपयोग होने के कारण पूरी नहीं हो पाती। समय पर काम पूरा नहीं होने से खर्चा बोझ बन कर रह जाता है। *(रा.प., 22.08.20)*

किसानों के अंगूठे लगवा बेचा यूरिया

बाड़मेर जिले के सेड़वा क्षेत्र में खाद बीज भण्डार संचालक ने 65 किसानों के अंगूठे लगवाकर 6 हजार यूरिया खाद के कट्टों की कालाबाजारी कर दी। शिकायत पर कलेक्टर ने जांच करवाई तो सामने आया कि किसानों को यूरिया खाद मिली ही नहीं, जबकि पोस मशीन से किसानों के नाम यूरिया खाद उठा ली। कलेक्टर के निर्देश पर यूरिया खाद का सत्यापन कराया गया तो यह सामने आया।

सत्यापन में यह भी सामने आया कि बीज लेने के दौरान किसानों के अंगूठे लगवा लिए बाद में यूरिया खाद के बिल पेश कर दिए। किसानों का आरोप है कि बीज लेने के दौरान अनभिज्ञ रखकर पोस मशीन पर यूरिया खाद के लिए अंगूठे करवा दिए। मामले की सेड़वा थाने में मीनाक्षी खाद बीज भंडार संचालक सुरेश कुमार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तथा पुलिस ने उसके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। *(रा.प., 15.09.20)*

कर्मचारी खा गए गरीबों का राशन

गरीब परिवारों को दो रुपए किलो गेहूं (कोरोना काल में निःशुल्क) देने के लिए सरकार खाद्य सुरक्षा सूची में नाम जोड़कर लाभ दे रही है। सरकार के निर्देश पर दौसा उपखण्ड अधिकारियों ने खाद्य सुरक्षा सूची की जांच कराई तो सामने आया कि करीब तीन हजार से अधिक लोग सरकारी कर्मचारी होने के बाद भी कई माह से गरीबों की खाद्य सामग्री (गेहूं) लेते सामने आए।

अब जिन कर्मचारियों के नाम मिले हैं, उनसे 27 रुपए प्रति किलो की दर से वसूली की जानी है। किस कर्मचारी ने कितने माह कितना गेहूं उठाया उसे उतनी राशि चुकानी पड़ेगी। उनसे करीब एक करोड़ रुपए से ज्यादा वसूली होनी है। *(रा.प., 09.08.20)*

परियोजनाएं नहीं हुई समय पर पूरी

प्रदेश में परवन परियोजना, नर्बदा जालोर परियोजना, आरओबी श्रीमहावीरजी, आपनी योजना फेज-2 व अन्य परियोजनाओं को पूरा करने में देरी से लागत बढ़ने का खामियाजा प्रदेश को सहन करना पड़ा है।

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के अनुसार पिछले साल के शुरू में प्रदेश की 43 अधूरी योजनाओं पर 125 अरब की लागत बढ़ गई, जबकि 88 परियोजनाएं 5 से 25 साल से अधूरी थीं और 28 परियोजनाओं पर कोई खर्च ही नहीं किया गया था। इस देरी की वजह से सरकार पर आर्थिक भार बढ़ गया। विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट से यह खुलासा हुआ है। *(रा.प., 20.09.20)*

मजाक बना दलबदल विरोधी कानून

राजनीति में 'आयाराम-गयाराम' की परिपाटी को रोकने के लिए 1985 में लाए गए सख्त दलबदल कानून के बावजूद 35 वर्षों से हम चुनी हुई सरकारों को धाराशाही होते देख रहे हैं। इस संबंध में चुनाव आयोग से लेकर संसद और तमाम राजनीतिक दल भी उस कानून के मजाक बनने के मूक दर्शक बने हुए हैं। नैतिक मूल्य और विचारों की प्रतिबद्धता के स्थान पर सत्ता पाने की प्रतिस्पर्धा हावी होती जा रही है।

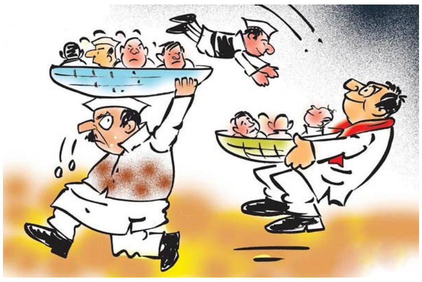

सरकारें गिराने के खेल में जब कानूनी अड़चने आने लगी तो विधायकों से इस्तीफा दिलाकर बहुमत को प्रभावित करने की परिपाटी शुरू हो गई। बड़ा सवाल ये है कि क्या इसे रोका जा सकता है? रोका जा सकता है तो कैसे? इसके लिए पहल कौन करेगा? *(रा.प., 18.07.20)*

नाममात्र की नसबंदी : करोड़ों का खर्च

जयपुर स्थित हीरा बाग के लेप्रोस्कोपिक स्टेटिक सेंटर पर नसबंदी करने का ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। हालात यह है कि जहां पर हर साल 700 पुरुष व महिला नसबंदी होती थी, वहीं अब नसबंदी 60 से 70 तक ही सिमट कर रह गई है। यहां दो डॉक्टर तो सालों से डेपुटेशन पर लगे हुए हैं।

चौंकाने वाली जानकारी यह है कि डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन, मेन्टीनेंस, बिजली-पानी के बिल और अन्य मदों पर हर साल करीबन एक करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। पैसे की बर्बादी रोकने के लिए सरकार द्वारा सेंटर को बन्द कर भवन को किसी अन्य काम में लिया जाना प्रस्तावित था। लेकिन अब संबंधित फाइल ही गुम हो गई है। *(दै.भा., 03.08.20)*

नियमों में फंसी आयुष्मान योजना

प्रदेश में 400 से अधिक निजी अस्पतालों में हर साल तीन लाख से अधिक इलाज लेने वाले भामाशाह कार्ड धारकों को अभी इलाज नहीं मिल पाएगा। वजह है निजी अस्पतालों की ओर से भामाशाह के तहत इलाज के लिए मना कर देना।

इसकी तीन प्रमुख वजह बताई जा रही है। जिसमें क्लीनिकल स्टेबलिश एक्ट में पंजीयन कराना, पुराना भुगतान जल्दी करना और निजी व सरकारी अस्पताल में भेदभाव नहीं करना शामिल है। वहीं सरकार ने अभी किसी भी कंपनी को टेंडर नहीं दिया है। ऐसे में अस्पतालों में पिछले चार महीनों से इलाज नहीं किया जा रहा है। सरकार ने एक आदेश जारी कर निजी अस्पतालों के लिए क्लीनिकल स्टेबलिश एक्ट में पंजीयन कराना अनिवार्य किया है।

(दै.भा., 13.07.20)

ग्यारह हजार क्विंटल मूंगफली गायब

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंगफली खरीद में अनियमितता पाए जाने पर सहकारिता विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने बीकानेर जिले के बज्जू, श्रीकोलायत एवं चूरू के तीन निरीक्षकों को निलम्बित कर दिय। इन तीनों खरीद केंद्रों पर करीब ग्यारह हजार क्विंटल मूंगफली का घोटाला हुआ है।

समर्थन मूल्य में गड़बड़ी की शिकायतों के बावजूद संबंधित निरीक्षकों ने आंखे मूंद रखी थी। अग्रवाल के अनुसार क्रय-विक्रय सहकारी समिति चूरू, बज्जू एवं कोलायत में समर्थन मूल्य खरीद 2019 में मूंगफली खरीद प्रकिया की जांच करवाने पर तीनों खरीद केंद्रों पर 10 हजार 835 क्विंटल मूंगफली कम पाई गई है। मूंगफली कहां गई और किसने खुर्दबुर्द की, इसे लेकर खरीद केंद्र के खिलाफ पुलिस थाने में मामला भी दर्ज करवाया गया है।

(रा.प., 16.07.20)

खाद बनाने की मशीनें हो रही कबाड़

प्रदेश की राजधानी के पार्कों में लगी खाद बनाने की मशीनें कबाड़ हो रही हैं। खाद बनाना तो दूर इन्हें शुरू भी नहीं किया जा रहा। हालात यह है कि कई पार्कों में से तो मशीनें चोरी तक हो गईं। कई पार्कों से मोटर तो कहीं तार चोरी हो गए। नगर निगम के अधिकारी इनकी देखरेख करने के बजाय बची हुई मशीनों को भी कबाड़ होते देख रहे हैं।

यह मशीनें नगर निगम ने वर्ष 2017 में स्वच्छता सर्वेक्षण के दौरान फूल-पत्तियों से जैविक खाद बनाने के लिए खरीदी थी। करीब 80 हजार रुपए प्रति मशीन की लागत से शहर के 70 पार्कों में करीब 60 लाख रुपए की लागत से मशीनें लगाई गई। *(रा.प., 22.07.20)*

आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपैया

राज्य की आर्थिक स्थिति चिंताजनक है। राज्य सरकार को रोजमर्रा के खर्चे उठाने के लिए भी उधार लेना पड़ रहा है। हालात यह है कि सरकार को जितना उधार सालभर में उठाना था, उसका 60 फीसदी कर्जा तो सिर्फ चार माह में उठाया जा चुका है। चार माह में राजस्व घाटा भी 138 प्रतिशत तक पहुंच गया है। राजस्व वसूली लगातार गिर रही है। अप्रेल से जुलाई तक के चार महीनों में राजस्व लगभग 21 प्रतिशत ही मिल पाया है।

यह खुलासा नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) को सौंपे गए आंकड़ों से हुआ है। आंकड़ों के अनुसार पहले चार माह में सालभर के कर राजस्व का 20 प्रतिशत हिस्सा भी राज्य सरकार को नहीं मिला है।

(रा.प., 22.09.20)

अटक गई नए जिले बनाने की कवायद

प्रदेश में बढ़ती आबादी के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था के लिए 6 वर्ष पहले शुरू हुई नए जिले बनाने की कवायद कागजों में अटक कर रह गई है। सेवानिवृत आइएएस परमेश चंद्र की अध्यक्षता वाली समिति ने 2018 में सरकार को नए जिले बनाने की सिफारिशें भेज दी मगर इस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है। इस बीच दो सरकारों ने कमान संभाली लेकिन रिपोर्ट पर जमी धूल नहीं हटी।

कमेटी की रिपोर्ट संबंधी मुद्दा 6 साल से सदन में व बाहर उठता रहा है। सरकार ने सदन में बताया था कि रिपोर्ट पर सिर्फ अध्यक्ष के हस्ताक्षर हैं। सूत्रों के अनुसार समिति ने 50 नए जिलों के प्रस्ताव पर विचार कर 5 नए जिलों की अनुशंसा की थी। *(रा.प., 16.07.20)*

राइट टू हेल्थ बिल अब ठंडे बस्ते में

प्रदेश में कोरोना काल और सियासी संग्राम के चलते राज्य सरकार का महत्वाकांक्षी प्रत्सावित राइट टू हेल्थ बिल अब ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना काल से पहले कहा जा रहा था कि बिल का मसौदा अंतिम चरण में है और जल्द ही इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन अब चार महीनों से इस बिल के संबंध में कोई हलचल दिखाई नहीं दे रही है। इस बिल को कांग्रेस ने विधान सभा चुनाव के जनघोषणा पत्र में शामिल किया था और सरकार बनते ही इस पर तत्परता से काम शुरू हुआ था। *(रा.प., 01.08.20)*

दस गुना महंगी खरीदी आयुर्वेदिक दवा

आयुर्वेद विभाग ने कोरोना महामारी के दौरान दवा खरीदने में सरकारी खजाने को 13.70 करोड़ रुपए की चपत लगा दी। तमाम नियम कायदों को ताक पर रखकर एक ही फर्म आईएमपीसीएल से दवाइयां खरीदी गई जिसकी कीमत बाजार मूल्य से 10 से 15 गुना तक ज्यादा थीं।

नियमानुसार पिछले तीन साल में किसी कंपनी की कोई भी दवा अमानक घोषित हुई हो, तो वह निविदा प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकती। जबकि आईएमपीसीएल कंपनी की दवा की जांच सरकारी मान्यता प्राप्त एनएबीएल लैब में कराने पर अमानक पाई गई थी। कंपनी ने झूंठा शपथ पत्र देकर इस तथ्य को छिपाया। इतना ही नहीं बल्कि बिना निविदा ही इम्यूनिटी बढ़ाने की 3.94 करोड़ रुपए की दवाईयों की खरीद का भी आर्डर दे दिया गया। जिससे सरकार को 99 लाख रुपए का नुकसान हुआ। *(दै.भा., 25.09.20)*

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की सफलता मे अंतर क्यों?

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शंस इंडेक्स 2019 में भारत एक वर्ष से पहले की रैंकिंग 78 से दो पायदान और नीचे 80 पर चला गया है। जहां यह इंडेक्स दर्शाता है कि देश में भ्रष्टाचार बेलगाम हो रहा है, वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों, प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग की बढ़ी व्यस्तता भी इसे सिद्ध करती है। बीते एक दशक के दौरान दोनों जांच एजेंसियों की सक्रियता अप्रत्याशित बढ़ी है, पर बेहद निचले स्तर पर सफलता दर सक्रियता की मंशा पर सवाल खड़े करती रही है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अक्सर 'सुपर' जांच एजेंसी भी कहा जाता है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन (रोकथाम) अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मार्च 2011 से जनवरी 2020 के बीच 1569 मामलों में छापेमारी की 1700 कार्रवाई की। लेकिन सफलता दर की हकीकत यह रही कि महज 9 मामलों में ही दोषसिद्धि हो पाई। ये भी ऐसे मामले हैं जिनके बारे में आम जन को पता भी नहीं। इससे ईडी की सक्रियता व सफलता में अंतर के आंकड़ों से सवाल उठते रहे हैं।

(रा.प., 24.07.20)

मूंगफली खरीद में घोटाला–जमा कराए एक करोड़

जोधपुर जिले की फलोदी क्रय-विक्रय सहकारी समिति में इस साल न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर मूंगफली की खरीद में 2.75 करोड़ रुपए का गबन सामने आने के बाद अब समिति के कार्मिकों व कम्प्यूटर ऑपरेटर ने 1.07 करोड़ रुपए नकद जमा कराए हैं। इन कर्मिकों का वेतन 15 हजार रुपए मासिक से अधिक नहीं है। फिर भी सहकारिता विभाग ने आयकर विभाग को सूचना नहीं दी। फलोदी समिति के अंतर्गत लोहावट के क्रय प्रभारी हरि सिंह, बापिणी के प्रेम सिंह, फलोदी के मोहन लाल चौधरी, कम्प्यूटर ऑपरेटर गणेश कुमावत व बाप के दिलीप सिंह राजपुरोहित ने मिलकर 1.07 करोड़ रुपए जमा कराए हैं।

मूंगफली की खरीद नवम्बर 2019 से मार्च 2020 तक हुई थी। फलोदी व बाप समिति ने नैफेड में 5 हजार क्विंटल मूंगफली कम जमा कराई। इसकी कीमत 2.75 करोड़ रुपए है। भौतिक सत्यापन में दोषी मिलने पर सरकार ने फलोदी व बाप समिति के मुख्य व्यवस्थापक (जीएम) मुरली मनोहर व्यास को पिछले माह निलंबित कर दिया। मामले की जांच जारी है। *(रा.प., 13.07.20)*

जेडीए में भ्रष्टाचार से निजात दिलाने वाला सिस्टम फेल

जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) में छाए भ्रष्टाचार से निजात दिलाने के लिए ऑनलाइन सिस्टम को बढ़ावा देने की पहल की जा रही है। सरकार की पहल पर जेडीए में आमजन से जुड़ी कुछ सर्विसेज को सीधे ऑनलाइन निपटाने की कसरत की गई है। हालांकि यहां अब लोगों को दोगुना परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो ऑनलाइन अप्लाई करना और फिर पहले की तरह ही अफसरों के देहरी ढोक व भेंट चढ़ाना।

जी हां, भ्रष्टाचार में लिप्त सिस्टम इस बात की पुरजोर कोशिश में लगा है कि ऑनलाइन सर्विसेज सफल नहीं हो और लोग उनके यहां चक्कर काटते रहें। सामने आया है कि ऑनलाइन पट्टे, नाम ट्रांसफर, लीज, सब-डिविजन के 500 से ज्यादा मामले जोन कार्यालय में पेंडिंग है। जेडीए के जोन उपायुक्तों से परेशान होकर कई मामले ऊपर प्रशासन तक पहुंचे हैं। *(दै.भा., 18.09.20)*

विगत तीन माह के दौरान रिश्वत लेते गिरफ्तार कुछ प्रकरणों की संक्षिप्त बानगियां

जिला	रिश्वत लेने वाले भ्रष्टाचारी का नाम	कार्यरत विभाग का नाम व पद	रिश्वत में ली राशि (रुपए में)	स्त्रोत
उदयपुर	आबिद खान आरिफ खान	वित्तीय सलाहकार, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, उदयपुर दलाल	2,00,000	रा.प., 11.07.20
जोधपुर	ओम प्रकाश मीणा	मैनेजर, एनटीपीसी लि., फलोदी	1,00,000	रा.प., 16.07.20
बांसवाड़ा	बहादुर सिंह मईड़ा मुकेश मईड़ा	सरपंच, बारी पंचायत समिति कंपाउंडर, छोटी सरवन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	1,11,000	दै.भा. एवं रा.प., 22.07.20
अजमेर	राहुल राघव	लाइजिंग ऑफीसर, एमआरएम कंपनी, अजमेर	50,000	रा.प. एवं दै.भा., 30.07.20
श्रीगंगानगर	अमृतलाल जीनगर अनिल विश्नोई	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, थाना रायसिंहनगर दलाल, श्रीकरणपुर	1,00,000	दै.भा. एवं रा.प., 05.08.20
कोटा	पंकज मंगल	अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका, रामगंजमंडी	1,00,000	दै.भा., 07.08.20
कोटा	बबली मीणा महावीर प्रसाद जैन	सरपंच, पंचायत समिति, मंडाना ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, मंडाना	20,000	दै.भा., 07.09.20
चित्तौड़गढ़	श्याम लाल चौहान जय प्रकाश शर्मा	क. तकनीकी सहायक, पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़ ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भैंसरोडगढ़	50,000	दै.भा., 11.09.20
भरतपुर	कपूर चंद वर्मा	सहायक अधीक्षक, डाकघर सब डिविजन, भरतपुर	30,000	रा.प., 18.09.20

सतत् विकास लक्ष्यों की योजना

हम दुनिया का कायाकल्प करने की दहलीज पर खड़े हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से 17 सतत् विकास लक्ष्यों की ऐतिहासिक योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक अधिक सम्पन्न, अधिक समतावादी और अधिक संरक्षित विश्व की रचना करना है। 17 सतत् विकास लक्ष्य और 169 उद्देश्य सतत् विकास के लिए 2030 एजेंडा के अंग हैं, जिसे सितंबर 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की शिखर बैठक में 193 सदस्य देशों ने अनुमोदित किया था जो पहली जनवरी 2016 से प्रभावी हुआ है।

सतत् विकास लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निम्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्रवाई के लिए प्रेरित किया जाएगा।

गरीबी, भुखमरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुशहाली, लैंगिक समानता, जल एवं स्वच्छता, ऊर्जा, आर्थिक वृद्धि और उत्कृष्ट कार्य, बुनियादी सुविधाएं, उद्योग एवं नवाचार, असमानताओं में कमी, संवहनीय शहर, उपभोग व उत्पादन, जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिक प्रणालियां, शांति एवं न्याय और भागीदारी।

सतत् विकास एजेंडा के मामले में भारत की प्रगति की कुंजी राज्य सरकारों के पास है और उनमें से अनेक ने इन लक्ष्यों पर अमल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

हमारी सोच और लक्ष्य

''एजेंडा 2030 के पीछे की हमारी सोच जितनी ऊँची है हमारे लक्ष्य भी उतने ही समग्र हैं। इनमें उन समस्याओं को प्राथमिकता दी गई है, जो पिछले कई दशकों से अनसुलझी हैं और इन लक्ष्यों से हमारे जीवन को निर्धारित करने वाले सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं के बारे में हमारे विकसित होती समझ की झलक मिलती है। मानवता के 1/6 हिस्से के सतत् विकास का विश्व और हमारे सुंदर पृथ्वी के लिए बहुत गहरा असर होगा।''

– नरेन्द्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री

कोई प्रवासी श्रमिक नहीं सोएगा भूखा

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना देश में रोजगार के लिए पलायन करने वाले श्रमिकों के लिए वरदान साबित हो रही है। वे पैतृक गांव या शहर को छोड़ जहां भी रोजगार के लिए जाएंगे, इस योजना के तहत वहीं से उन्हें मासिक राशन उपलब्ध हो जाएगा।

योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत 81 करोड़ लाभान्वितों को देशभर में कहीं से भी राशन प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इससे किसी भी श्रमिक को नौकरी छूटने या कोरोना जैसी महामारी में भूखा सोने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। यह योजना 20 राज्यों में लागू हो चुकी है। बाकी राज्यों में त्वरित स्तर पर लागू करने की तैयारी है।

(रा.प., 02.07.20)

खेती–किसानी का डिजिटलीकरण

कोरोना काल के दौरान खाद की बिक्री ने नया रिकार्ड कायम किया है। लेकिन इस क्षेत्र में पारदर्शिता की कमी के चलते कई गोरखधंधे सामने आए हैं। मद्देनजर केंद्र सरकार अब खेती–किसानी क्षेत्र का भी पूरी तरह से डिजिटलीकरण करने जा रही है। शुरुआत उर्वरकों की खरीद–बिक्री से की जा रही है। अब उर्वरकों की खरीद–बिक्री का भुगतान सिर्फ ऑनलाइन हो सकेगा, जिससे कालाबाजारी पर रोक लगेगी।

किसान भुगतान करते वक्त क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकेगा। इससे किसानों से अधिकतम खुदरा मूल्य से एक पैसा भी ज्यादा नहीं लिया जा सकेगा। खरीद पर सरकारी अनुदान राशि भी पारदर्शी तरीके से किसान के खाते में पहुंचेगी। *(रा.प., 08.08.20)*

प्लास्टिक कचरे से निपटना आवश्यक

सिंगल यूज प्लास्टिक आज भारत सहित पूरे विश्व के समक्ष एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। यह विश्व में एक कचरे के रूप में फैला हुआ है। यह हमारे पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बना हुआ है। भारत में प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए सतत् कार्ययोजनाएं बनाई गई हैं और जनमानस को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाया जा रहा है। प्लास्टिक कचरे को घरों, कार्यालयों व संस्थानों से एकत्रित कर उचित माध्यम से रिसाइकिल करने का रास्ता निकाला जा रहा है।

देश में प्लास्टिक बैंकों की स्थापना के लिए तेजी से काम शुरू किया जा रहा है। देहरादून में कोरोनाकाल से पहले 10 प्लास्टिक बैंक स्थापित हो चुके थे। इनके माध्यम से तीन माह में लगभग तीन हजार किलोग्राम प्लास्टिक कचरा भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के हवाले किया जा चुका है। संस्थान इस कचरे का उपयोग डीजल बनाने के लिए कर रहा है। देशभर में ऐसे सतत् एवं सरल प्रयोगों के जरिए बदलाव लाया जा रहा है।

(जाग., 14.09.20)

रंग लाई जैविक खेती की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जहरीले खाद और कीटनाशक वाली खेती छोड़ने के लिए की गई अपील रंग लाने लगी है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के मुताबिक अब तक देश में 19 लाख से भी ज्यादा किसान जैविक खेती से जुड़ चुके हैं। सरकार अब जैविक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है। इसके लिए परम्परागत कृषि विकास योजना बनाई गई है।

इस योजना के तहत प्राकृतिक खेती के लिए केंद्र सरकार तीन साल के लिए प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपए की सहायता दे रही है। कृषि मंत्री तोमर के मुताबिक देश में ऑर्गेनिक खाद का उत्पादन बढ़ रहा है और किसान स्वेच्छा से परम्परागत खेती से जुड़ रहे हैं। *(रा.प., 27.09.20)*

करदाताओं को मिले कई अधिकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करदाताओं के लिए नया प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन, ऑनरिंग द ऑनेस्ट(पारदर्शी कराधान-ईमानदार का सम्मान) लॉन्च किया है। इसमें तीन बड़े सुधार- फेसलैस एसेसमेंट, करदाता चार्टर और फेसलैस अपील शामिल है। टैक्स चार्टर के तहत करदाताओं को कई अधिकार दिए गए हैं। इनमें करदाता को ईमानदार माने जाने का अधिकार शामिल है, जब तक उस पर शक करने का मजबूत आधार न हो। करदाता अब यह भी जान सकेंगे कि राजस्व विभाग के पास उनके बारे में क्या-क्या जानकारी है।

फेसलैस असेसमेंट के तहत अब आयकर अधिकारी नहीं बल्कि कंम्प्यूटर जांच करेगा। रिटर्न फाइल करने पर आयकर अधिकारी किसी को बेवजह परेशान नहीं कर सकेंगे। इससे अफसरों की जवाबदेही तय होगी। फेसलैस अपील में भी अधिकारी और अपीलकर्ता आमने-सामने नहीं होंगे। *(रा.प., 14.08.20)*

'प्लग एंड प्ले' से खुलेगी की राह

उद्योग चलाने की प्रतिभा है लेकिन बड़ी पूंजी नहीं है, ऐसे प्रतिभाशाली लोगों के लिए अच्छी खबर है। ऐसे लोगों को खुद के उद्योग से जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने पहली बार 'प्लग एंड प्ले' कंसेप्ट और छोटे औद्योगिक भूखण्ड पैटर्न लागू किया है।

इसके तहत औद्योगिक गतिविधि शुरू करने के लिए रीको खुद अत्याधुनिक ईमारत उपलब्ध कराएगा। सूक्ष्म व लघु उद्योग संचालक वहां सीधे काम शुरू कर सकेंगे। योजना में 250 वर्गमीटर के भूखण्ड भी उपलब्ध होंगे। इससे कम एरिया और छोटी पूंजी में कारोबार आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसकी शुरुआत जयपुर से होगी। जबकि छोटे भूखण्डों की योजना उनियारा और किशनगढ़ के पास रघुनाथपुरा में लांच होगी। *(रा.प., 17.07.20)*

इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कांफ्रेस के माध्यम से 300 करोड़ रुपए की लागत से स्वास्थ्य सेवाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इसमें 29 भवनों का लोकार्पण तथा 8 निर्माण कार्यों का शिलान्यास शामिल है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं विकसित करने पर जोर देते हुए गहलोत ने कहा कि हमारा सपना है कि प्रदेश से किसी भी व्यक्ति को इलाज के लिए बाहर नहीं जाना पड़े।

गहलोत ने कहा कि पिछले एक साल में 15 जिलों को मेडिकल कॉलेज मिले हैं, इनको मिलाकर राजकीय क्षेत्र में 31 मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। हमारी मंशा है सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलें। उन्होंने कहा राजस्थान चिकित्सा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गया है। कोरोना के मुकाबले में हमारे प्रबंधन की देशभर में सराहना हुई है। *(दै.भा., 20.08.20)*

बैंकों के हाल सुधरने में लगेंगे तीन साल

भारतीय बैंकिंग सिस्टम पर रेटिंग एजेंसी एसएंडपी ने एक अनुमान जारी किया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण बिगड़े भारतीय बैंकों का हाल सुधरने में कम से कम 3 साल या उससे भी अधिक समय लग सकता है। एजेंसी ने कहा रिकवरी के मामले में भारत अन्य देशों के मुकाबले सबसे नीचे रहेगा।

एजेंसी ने भारतीय बैंकों और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए नेगेटिव रिपोर्ट दी है। क्योंकि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुई स्थितियों से बैंकों का ऑपरेशन धीमा हुआ है। बैंकों को बढ़ते एनपीए से निपटने के भी प्रयास करने होंगे। एजेंसी ने रिकवरी का अनुमान लगाने के लिए ग्लोबल लेवल पर 20 सबसे बड़े बैंकिंग सिस्टम का विश्लेषण किया। *(रा.प., 26.09.20)*

कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत

कोरोनाकाल में राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत एक लाख करोड़ रुपए की वित्त पोषण सुविधा शुरू की। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का हिस्सा है। यह कोष कृषि-उद्यमियों, स्टार्टअप्स, कृषि क्षेत्र की प्रौद्योगिकी कंपनियों और कटाई बाद फसल प्रबंधन में किसान समूहों की मदद के लिए बनाया गया है। योजना के तहत 8.55 करोड़ से अधिक किसानों को 17100 करोड़ रुपए की छठी किस्त भी जारी की गई है।

इस फंड से गांव के किसान समूहों, समितियों व एफपीओ को वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज बनाने, फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग लगाने के लिए एक लाख करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। *(दै.भा., 10.08.20)*

शहरी रोजगार योजना लाने की तैयारी

मोदी सरकार रोजगार के लिहाज से एक बड़ा कदम उठा सकती है। कोरोना से निपटने के अगले आर्थिक पैकेज के तहत शहरों और कस्बों में रोजगार की योजना शुरू करने की तैयारी की जा रही है। अर्थव्यवस्था के दूसरे क्षेत्रों के लिए भी इस पैकेज में बड़े प्रावधान होंगे।

वरिष्ठ सरकारी सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्दी ही सरकार दूसरा आर्थिक पैकेज लाने की तैयारी में है। इसमें सबसे अधिक जोर लोगों में अर्थव्यवस्था पर विश्वास कायम करने पर होगा, ताकि वे खर्च करने लगें और कारोबार पटरी पर लौटे। *(रा.प., 26.09.20)*

दस में से एक व्यक्ति है बेरोजगार

देश में रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं। कई राज्य संकट के दौर से गुजर रहे हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइ) के द्वारा जारी बेरोजगारी के नए आंकड़ों ने सभी को निराश किया है। अगस्त में शहरी बेरोजगारी 10 फीसदी के पास रही। फॉर्मल सेक्टर में भी इस महीने भारत की बेरोजगारी दर का सबसे बुरा हाल रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में अगस्त में बेरोजगारी की दर 7.65 फीसदी रही, जो जुलाई माह में 6.66 फीसदी के मुकाबले अधिक है।

लॉकडाउन में मिली छूट के चलते अनुमान था कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, लेकिन सीएमआई द्वारा जारी बेरोजगारी के आंकड़े अगस्त में भी बेहतर नहीं आए। आंकड़ों के मुताबिक, शहरी बेरोजगारी की दर जुलाई में 9.15 फीसदी रही थी, लेकिन अगस्त में यह आंकड़ा बढ़कर 9.83 फीसदी हो गया। *(रा.प., 03.09.20)*

सबसे महंगी हमारी बिजली

महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के बाद हमारी बिजली सबसे महंगी है। बिजली बिल (सरचार्ज, सेस सहित) में बेतहाशा बढ़ोतरी के मामले में राजस्थान देश में तीसरे पायदान पर पहुंच गया है। चिन्हित घरेलू श्रेणी में महाराष्ट्र व मध्यप्रदेश एवं कृषि श्रेणी में महाराष्ट्र व बिहार के बाद राजस्थान अव्वल है।

यहां 500 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ता को हर माह 4190 रुपए देने पड़ रहे हैं। जबकि पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा के शहरों में यह शुल्क 3300 रुपए से 3840 रुपए तक है। दिल्ली में तो घरेलू उपभोक्ता स्लैब में दर 2.73 रुपए प्रति यूनिट तक कम है। टैरिफ के अलावा 5 सरचार्ज-कर (अरबन सेस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, जल संरक्षण उपकर, फ्यूल सरचार्ज व अडानी भुगतान भार) का बोझ उपभोक्ता पर है। *(रा.प., 10.09.20)*

उपभोक्ता हित में होंगे कई प्रावधान

ऊर्जा मंत्रालय ने इलेक्ट्रिसिटी (राइट्स ऑफ कंन्ज्यूमर्स) रूल्स 2020 का ड्राफ्ट जारी किया है। जिसमें उपभोक्ता हित में कई महत्वपूर्ण प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। इस ड्राफ्ट पर उपभोक्ता, प्रदेश के तीनों डिस्कॉम एवं विद्युत उत्पादन व प्रसारण कंपनियां आपत्ति-सुझाव दे सकेंगे। इसके बाद इस पर मुहर लगेगी।

ड्राफ्ट के प्रावधानों के अनुसार बिजली उपभोक्ताओं को अब न केवल स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सुविधा मिलेगी बल्कि उन्हें विद्युत वितरण कंपनियों की औसतन बिल जारी करने की मनमानी से भी छुटकारा मिलेगा। इस ड्राफ्ट में डिस्कॉम पर शहरी इलाके में 24 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में अधिकतम 72 घंटे में खराब मीटर को बदलने, बिल भुगतान तिथि से कम से कम 10 दिन पहले उपभोक्ता तक पहुंचाने जैसे कई प्रावधान शामिल किए हैं।

(रा.प., 11.09.20)

भूमिगत नहीं हो पाए बिजली के तार

जयपुर की चारदीवारी के बाजार आज भी तारों के जाल से अटे पड़े हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बजट आवंटन और टेंडर के बाद भी तीन साल से यहां जाल बिछा हुआ है। मानसून के दिनों में अक्सर ये तार खतरे की घंटी बन जाते हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत चारदीवारी के एक हिस्से में बिजली के तारों को भूमिगत करने के लिए 33 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया था।

पहले चरण के लिए 16.81 करोड़ रुपए व दूसरे चरण के लिए 17.9 करोड़ रुपए दिए गए। स्मार्ट सिटी ने यह बजट जयपुर डिस्कॉम को दिए। जयपुर डिस्कॉम ने इसके लिए टेंडर भी कर दिए। लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। *(रा.प., 13.07.20)*

घरों में लगेंगे बिजली के स्मार्ट मीटर

प्रदेश में 500 करोड़ रुपए खर्च कर 6 लाख उपभोक्ताओं के घरों में बिजली के कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी की ओर से स्मार्ट मीटर के टेंडर की जांच को क्लीनचिट मिलने के बाद जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्कॉम ने कंपनियों को सप्लाई आर्डर दे दिया है। इससे बिजली चोरी पर लगाम लग सकेगी।

अगले महीने से स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। स्मार्ट मीटर में मोबाइल की तरह सिम लगी होगी, इससे पूरा मीटर ही ऑनलाइन रहेगा। मीटर रीडिंग, लोड वोल्टेज, डिसकनेक्शन-रीकनेक्शन, बिजली सप्लाई सहित अन्य कार्य मॉनिटरिंग इंजीनियर दफ्तर में बैठकर कर सकेंगे। *(दै.भा., 08.07.20)*

नहीं बन पाई कृषि विद्युत नीति

प्रदेश में 16 लाख किसानों को बिजली टैरिफ, स्थाई शुल्क, लोड, कनेक्शन और सप्लाई बढ़ाने सहित अन्य मुद्दों को लेकर बनने वाली नई 'कृषि विद्युत नीति' डेढ़ साल बाद भी फाइलों से बाहर नहीं निकल पाई है। इसका किसानों को सीधा नुकसान हो रहा है।

नई कृषि विद्युत नीति जारी नहीं होने से प्रदेश के 13.70 लाख किसान परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। वहीं सामान्य श्रेणी में कृषि कनेक्शन के लिए फरवरी 2012 से दिसम्बर 2019 तक के 3.12 लाख आवेदन बकाया हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर, जोधपुर व अजमेर डिस्कॉम की ओर से कृषि कनेक्शन देने का भार उठाने में असमर्थता जाहिर की है। इसके बाद नीति को पेंडिंग फाइल में डाल दिया गया है। *(दै.भा., 05.09.20)*

सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्लांट

महंगे बिजली बिलों से निजात पाने के लिए राजधानी जयपुर में सरकारी भवनों पर रूफटॉप सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित करने की शुरुआत हुई है। लेकिन जिस गति से इस दिशा में बढ़ना चाहिए उस गति से विभाग आगे नहीं बढ़ रहे हैं।

सरकारी भवनों पर जरूरत के मुताबिक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर विभाग बिजली बिल में सालाना करोड़ों रुपए की बचत कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर विभाग इस मामले में पूरी तरह उदासीन हैं। जेडीए कार्यालय और एसएमएस मेडिकल परिसर में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं, जिनसे प्रति वर्ष करोड़ों रुपए की बिजली खर्च में कमी आई है। इसी तरह प्रदेश में सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगने से सरकारी खर्च में करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है। *(रा.प., 04.08.20)*

सौर ऊर्जा से लाभान्वित होंगे किसान

कोरोना काल और मानसून की बेरुखी से टूट रहे किसानों के सपनों को फिर से संजोने का काम पीएम कुसुम (सौर ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान) योजना के तहत होगा। सरकार ने प्रदेश में योजना के तहत चयनित 723 किसानों की सूची जारी कर दी है। जिसके तहत किसानों को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए अपनी सहमति देनी होगी।

सभी किसान योजना से लाभान्वित हो सके इसके लिए योजना में बदलाव किया गया है। खास बात यह है कि किसान खेत की सिंचाई के साथ-साथ सौर ऊर्जा से तैयार बिजली सरकार को बेच भी सकता है। सोलर पंप सेट पर 60 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। साथ ही किसान को सोलर प्लांट लगाने के लिए छूट भी मिलेगी। किसानों को बैंक की ओर से आसान ऋण सुविधा भी देय है। *(रा.प., 20.07.20)*

कोरोना में उलझा लोगों का पानी

राज्य सरकार ने बीसलपुर बांध से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए एक हजार करोड़ रुपए की लागत के छह प्रोजेक्ट स्वीकृत किए थे। जयपुर शहर के जगतपुरा, खो-नागोरियान, आमेर, और जामडोली में चल रहे चार प्रोजेक्ट को इस साल के अंत तक पूरा कर आगामी गर्मियों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए विभाग मशक्कत कर रहा था। इसी बीच कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी और सभी प्रोजेक्ट पर ब्रेक लग गया।

इस स्थिति में अब इन प्रोजेक्ट में पांच-छह महीने का समय अतिरिक्त लगना तय माना जा रहा है। इससे इन क्षेत्रों के लोगों की उम्मीद भी कुछ महीने आगे खिसक गई। जगतपुरा-महल रोड पेयजल प्रोजेक्ट का काम 75 प्रतिशत ही पूरा हुआ है। अन्य तीन प्रोजेक्ट का काम धीमी गति के चलते महज 50 प्रतिशत तक ही हुआ है। *(रा.प., 06.07.20)*

पेयजल के लिए भरना होगा फार्म

जलदाय विभाग ने प्रदेशभर में अवैध पेयजल कनेक्शन पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इसके लिए 12 साल पहले बंद की गई एल फार्म की अनिवार्यता को फिर से शुरू किया जा रहा है। पेयजल कनेक्शन के लिए संबंधित अभियंता कार्यालय में फाइल मंजूर करानी होगी।

अभियंता कार्यालय से रजिस्टर्ड प्लंबर ही कनेक्शन करने के लिए उपभोक्ता के घर जाएगा। पेयजल कनेक्शन के लिए किस तरह का पाइप, मीटर व अन्य उपकरण गुणवत्ता के हैं या नहीं, वह तय करेगा। कनेक्शन के बाद रजिस्टर्ड प्लंबर उस फार्म को भरेगा और प्रमाणित करेगा कि पेयजल कनेक्शन नियमानुसार किया गया है। *(रा.प., 12.08.20)*

चार महीने का बिल एक साथ थोपा

प्रदेश में जलदाय विभाग ने 30 लाख पेयजल उपभोक्ताओं को चुपचाप बड़ा झटका दिया है। उपभोक्ता लॉकडाउन के सदमें से उबरते, उससे पहले ही जलदाय विभाग ने पेयजल उपभोक्ताओं को लॉकडाउन के दौरान के चार महीनों के बिल जुलाई और उसके बाद बिलों में समायोजित करने की जगह एक साथ जारी किए हैं। अब उपभोक्ता पेशोपस में है कि खराब आर्थिक हालत के चलते किस तरह से एक साथ चार महीनों के बिलों को चुकाएं।

जलदाय विभाग ने राहत की बात कहते हुए पहले मार्च से जून के बिलों को जुलाई और इसके बाद आने वाले बिलों में समायोजित करने की बात कही थी। उपभोक्ताओं ने इससे राहत की सांस ली थी कि चार माह के बिल एक साथ नहीं आएंगे। लेकिन इन आदेशों को गुपचुप बदल दिया गया। *(रा.प., 05.09.20)*

घर-घर कनेक्शन में जयपुर सबसे पीछे

प्रदेश में जल जीवन मिशन की बेहद कमजोर मॉनिटरिंग हो रही है। इसका नतीजा यह रहा कि बजट उपलब्ध होते हुए भी मिशन के तहत पेयजल कनेक्शन में जयपुर रीजन द्वितीय सबसे पीछे रह गया है। यहां सितंबर माह तक वार्षिक कार्ययोजना तय लक्ष्यों के मुकाबले महज 10 प्रतिशत यानी साढ़े तीन हजार ही पेयजल कनेक्शन हो सके हैं।

वहीं, संभागीय जिले कोटा, भरतपुर, अजमेर और जोधपुर में भी पेयजल कनेक्शन की रफ्तार धीमी है। अब विभाग के ही अफसर सवाल उठा रहे हैं कि यदि कनेक्शन की चाल यही रही तो इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख कनेक्शन कैसे होंगे। मिशन के तहत अन्य जिलों के मुकाबले जयपुर को 153 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत हुआ है। जयपुर रीजन प्रथम तो कनेक्शन के मामले में ठीक चल रहा है, लेकिन जयपुर रीजन द्वितीय प्रगति नहीं कर सका। *(रा.प., 09.09.20)*

छोटे जिलों में बेहतर काम

जल जीवन मिशन के तहत घरों में सरकारी नल से पानी पहुंचाने का काम मिशन मोड में न होकर रूटीन काम काज की तरह हो रहा है। स्थिति ऐसी है कि प्रदेश में छोटे जिलों में कनेक्शन जारी करने को लेकर बेहतर काम हो रहा है वहीं संभाग स्तर के जिले कनेक्शन देने में कछुआ चाल से भी धीमे साबित हो रहे हैं।

कुछ जिले ऐसे भी हैं जहां 500 से भी कम कनेक्शन हुए हैं। बीते एक महीने में 85 हजार घरों में मिशन के तहत सरकारी नल कनेक्शन हुए हैं। इस स्थिति में अब संशय हो रहा है कि कनेक्शन जारी करने की गति यही रही तो इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख नल कनेक्शन कैसे जारी होंगे। *(रा.प., 20.07.20)*

बांधों और नहरों की होगी मरम्मत

राजस्थान वॉटर सेक्टर लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के तहत जल संसाधन विभाग के अधीन 835 बांधों की मरम्मत का काम किया जा रहा है। इसके पहले चरण के लिए राज्य सरकार ने 1069 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। प्रोजेक्ट के तहत 39 बांधों की मरम्मत का काम चल रहा है।

प्रोजेक्ट में नहरों की मरम्मत भी की जा रही है। साथ ही आगामी दिनों में बांधों और नहरों की मरम्मत के लिए 26 नये कार्य शुरू किए जाएंगे। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार विभाग के अधीन 22 बड़े बांध, 84 मध्यम और 729 लघु श्रेणी के बांध हैं। *(रा.प., 19.09.20)*

पानी के मीटर बदलने पर ब्रेक

राजधानी जयपुर में अमृत मिशन के तहत बजट नहीं मिलने से चारदीवारी और इसके बाहर के इलाकों में 77 हजार पानी के पुराने मीटर और 36 किलोमीटर की जर्जर हो चुकी पेयजल लाइनों के बदलने पर ब्रेक लग गया है। अभी स्थिति ऐसी है कि जलदाय विभाग निगम को रोडकट के लिए 2 करोड़ 82 लाख रुपए की जगह पर महज 50 लाख रुपए ही दे पाया है।

अगर प्रदेशभर की बात करें तो अमृत मिशन के तहत प्रदेश के 26 शहरों में सीवरेज, ग्रीन स्पेस, पेयजल आपूर्ति, ड्रेनेज और शहरी यातायात के लिए 3224 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया था, लेकिन केंद्र से मिशन के तहत 293 करोड़ रुपए की तीसरी किश्त भी अभी तक नहीं मिली है। इससे जयपुर समेत पूरे प्रदेश में अमृत मिशन के तहत काम की रफ्तार धीमी हुई है। मिशन के तहत 23 शहरों में पेयजल योजनाओं के 24 कार्यों के कार्यादेश जारी किए गए हैं। जिसके तहत 3174 किलोमीटर की लाइनें बदली जाएंगी। *(रा.प., 10.08.20)*

घातक है बालविवाह की परम्परा

भारत में बाल विवाह अपराध है, फिर भी यह कुरीति देश के कई हिस्सों में अभी भी व्याप्त है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार राजस्थान में एक तिहाई किशोरियों की शादी 18 साल से पहले कर दी जाती है। बाल विवाह ने जटिलताओं के साथ किशोरियों को गर्भवती होने के जोखिम में डाल दिया है। नतीजतन उच्च मृत्युदर, कुपोषित मां, कुपोषित बच्चे जैसी कई संभावनाएं बढ़ गई हैं।

सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 15 से 19 वर्ष की आयु की 8 प्रतिशत महिलाए मां बन जाती हैं। राजस्थान में यह आंकड़ा 6 फीसदी है। एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए 18 से कम उम्र में किशोरियां शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार नहीं होती। इससे गर्भपात की संभावना बढ़ती है। *(दै.भा., 26.09.20)*

शादी के लिए उम्र तय करने पर विचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार लड़कियों की न्यूनतम शादी की उम्र पर फिर से विचार करने जा रही है। वर्तमान में यह 18 वर्ष है। इसके लिए समिति गठित की गई है जिसकी रिपोर्ट आने के बाद केंद्र सरकार निर्णय लेगी।

उन्होंने बताया कि केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय मातृ मृत्यु दर को कम करने और महिलाओं व बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के उपाय के रूप में महिलाओं की शादी की न्यूनतम उम्र को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने की संभावनाओं पर विचार कर रही है। इसके लिए एक टॉस्क फोर्स का गठन किया गया है। मोदी ने कहा कि सरकार महिलाओं के स्वास्थ्य सुधार के लिए कई कदम उठा रही है। *(रा.प., 17.08.20)*

प्रसूताओं पर भारी पड़ा कोरोना काल

प्रदेश में कोरोना काल के छह महीने प्रसूताओं पर भारी पड़े। इस दौरान करीब दो लाख से अधिक प्रसूताओं को प्रसव से पहले अस्पताल में जगह हासिल करने और खौफ के माहौल में यहां से वहां चक्कर लगाने को मजबूर होना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में कई निजी अस्पतालों ने सामान्य प्रसूताओं को भी आसानी से जगह नहीं दी और प्रसव कराने से इनकार किया।

जयपुर शहर के चारदीवारी क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित करने और इस क्षेत्र की प्रसूता का प्रसव कोविड डेडिकेटेड महिला चिकित्सालय सांगानेरी गेट में कर दिया गया। मजबूरन प्रसूता और परिवारजन डरते-डरते वहां गए और प्रसव करवाया। शिकायत यह भी रही कि अस्पताल में भर्ती होने के बाद महिलाएं संक्रमित हो गईं। *(रा.प., 26.09.20)*

आंगनबाड़ी पर बनेंगे न्यूट्री गार्डन

प्रदेशभर की 62 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण वाटिका अभियान की शुरुआत होगी, ताकि नौनिहालों के कुपोषण को दूर किया जा सके। बजाज नगर स्थित समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री ममता भूपेश ने फलदार, छायादार पौधे लगाकर पोषण वाटिका अभियान की शुरुआत की।

विभाग के मुताबिक 30 जुलाई से 15 अगस्त तक के पखवाड़े में चयनित सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पौधारोपण कार्यक्रम के तहत न्यूट्री गार्डन विकसित किए जाएंगे। चयनित केंद्रों पर क्यारियां बनाकर मौसमी सब्जियां लगाएंगे। इसके लिए 27.85 लाख रुपए का बजट रखा गया है। *(रा.प. एवं दै.भा., 29.07.20)*

एक कमरे में प्री-प्राइमरी कक्षा

देशभर में हाल ही जारी नई शिक्षा नीति के तहत प्रदेश के 62 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों में ही प्री-प्राइमरी की कक्षाएं शुरू होनी है। पड़ताल में सामने आया है कि कुल 62020 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 61593 केंद्र संचालित है जो केवल ढ़ाई हजार शिक्षकों के भरोसे हैं।

इनमें से 35 हजार केंद्रों के पास खुद का भवन नहीं हैं। 27318 केंद्रों में शौचालय नहीं हैं। 13186 केंद्रों में पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हैं। 10553 किराए के भवनों में, 18565 सरकारी स्कूलों में, 4020 अन्य सरकारी भवनों में तथा 2645 सामुदायिक भवनों व मंदिरों में संचालित है। करीब करीब सभी केंद्र एक कमरे में चल रहे हैं, जहां बच्चों के बैठने व पाठन सामग्री तक की व्यवस्था नहीं है। इन केंद्रों की दशा सुधारने पर ध्यान देना होगा। *(दै.भा., 19.08.20)*

महिलाओं में कोरोना का खतरा कम

पुरुषों की तुलना में महिलाएं कोरोना पॉजिटिव कम हो रही हैं। इसकी पुष्टि रिसर्च और स्टडी ही नहीं, पॉजिटिव केसों के आंकड़े भी कर रहे हैं। जयपुर के कोरोना पॉजिटिव में 70 प्रतिशत पुरुष और सिर्फ 30 प्रतिशत महिलाएं हैं। हालांकि, इसकी वजह महिलाओं का घर से कम बाहर निकलना माना जा रहा है। लेकिन हाल ही में दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित जर्नल नेचर ने महिलाओं में कोरोना संक्रमण कम होने की वजह उनकी मजबूत रोग-प्रतिरोधक क्षमता बताई है।

जयपुर के रिसर्चर डॉ. अरविंद गुप्ता ने बताया कि महिलाओं में रोग-प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने वाले टी-सैल्स ज्यादा मौजूद होते हैं। ये टी-सैल्स उनमें तीव्र गति से बनते हैं। उनमें उम्र के हिसाब से भी यह सैल्स घटते नहीं हैं। *(दै.भा., 02.09.20)*

कैसे होगी पढ़ाई के नुकसान की भरपाई ?

विशेषज्ञों का मानना है कि गरीब बच्चों और लड़कियों की पढ़ाई पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर पड़ा है। लॉकडाउन के कारण दुनियाभर में करीब 150 करोड़ बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया है। भारत में स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या करीब 33 करोड़ है।

लॉकडाउन और अनलॉक के चलते स्कूल बंद हैं। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाने की व्यवस्थाएं नहीं हैं। इनमें सिर्फ 10.3 फीसदी विद्यार्थियों के पास ही ऑनलाइन पढ़ने की व्यवस्था है। केंद्र ने स्कूलों को खोलने को लेकर कई तरह की गाइडलाइन जारी की है, उनमें सोशल डिस्टेंसिंग व सेनेटाइजेशन के नियम हैं। स्कूलों में सिर्फ 30 से 40 प्रतिशत की स्ट्रेंथ रखने की भी बात है। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई दूभर हो गई है। *(दै.भा., 19.07.20)*

नियमों को लेकर किया जागरूक

मोटर यान (संशोधन) अधिनियम 2019 के प्रदेश में लागू होने के बाद पुलिस ने जन जागरूकता अभियान चलाया। जयपुर शहर की यातायात और थाना पुलिस ने शहर के अलग-अलग प्वाइंटों पर वाहन चालकों को एमवी एक्ट के संशोधनों और जुर्माने के नए प्रावधानों के बारे में बताया और वाहन चालकों से यातायात नियमों की पालना की अपील भी की। इसके अलावा राजस्थान महामारी अध्यादेश और कोरोना से बचाव के लिए भी लोगों को जागरूक किया।

अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम अजय पाल लाम्बा ने विशेष नाकाबंदी भी करवाई। इस दौरान थानाधिकारी स्वयं प्वाइंट पर रहे और लोगों को नए मोटर यान अधिनियम तथा संबंधित यातायात नियमों की जानकारी दी।

(रा.प., 10.07.20)

जुर्माना घटाकर मोटर व्हीकल एक्ट लागू

प्रदेश सरकार ने आखिरकार 10 माह बाद संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के जुर्माने लागू कर दिए। राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित जुर्माने प्रदेश सरकार ने दस गुना तक कम कर दिए हैं। जैसे रोड लाइट जम्प करने पर केंद्र सरकार ने 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था, उसे घटाकर 1000 रुपए किया है।

शराब पीकर गाड़ी चलाने पर केंद्र सरकार ने 10 हजार रुपए जुर्माना और 6 माह की सजा का प्रावधान किया था, उसे राज्य सरकार ने 10 हजार रुपए सीमित कर दिया।

ओवरलोडिंग वाहनों पर अब 40 हजार रुपए का जुर्माना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ इस पर चर्चा कर प्रस्ताव को मंजूरी दी है। *(दै.भा., 09.07.20)*

ब्रांडेड हेलमेट पहनना अनिवार्य

अब बाजार में ब्रांडेड हेलमेट बेचना और पहनना जरूरी होगा। ऐसा नहीं करने पर दोनों मामलों में कार्यवाही होगी। केंद्र सरकार दुपहिया वाहन पर सवार लोगों के लिए सिर्फ ब्रांडेड हेलमेट पहनने, उत्पादन व बिक्री सुनिश्चित करने के लिए नया कानून लागू करने जा रही है।

लोकल हेलमेट पहन कर बाहर निकलने पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। लोकल हेलमेट उत्पादन पर दो लाख रुपए का जुर्माना व जेल की सजा का प्रावधान किया जाएगा। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने बाइक सवारों को सुरक्षित हेलमेट मुहैया कराने के लिए पहली बार इसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीएसआई) की सूची में शामिल किया है।

(रा.प. एवं दै.भा., 02.08.20)

सड़क पर पैदल चलना भी असुरक्षित

प्रदेश में वाहनों की बढ़ती संख्या और ड्राइविंग नियमों की पालना नहीं होने की वजह से सड़कों पर पैदल चलना भी सुरक्षित नहीं है। हर साल सड़क हादसों में मरने वाले 10 हजार 320 लोगों में से पैदल चलने वाले 1448 लोगों की मौत हो रही है। हालांकि पहले नंबर पर दुपहिया पर चलने वालों की तो दूसरे नंबर पर कार-टैक्सी से सफर करने वाले सड़क हादसों में मर रहे हैं। साईकिल पर चलने वाले 63 लोगों की मौत हुई है।

यह जानकारी हाल में परिवहन विभाग के सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ द्वारा 2018 के सड़क हादसों पर जारी रिपोर्ट से सामने आई है। पैदल चलने वालों की मौत के कारणों में सड़क के दोनों ओर सही तरीके के फुटपाथ का नहीं होना, उन पर व्यापारियों का अतिक्रमण होना, वाहन चालकों द्वारा जैब्रा क्रॉसिंग पर गाड़ी खड़ी कर देना। यातायात नियमों का पालन नहीं करना आदि मुख्य हैं। *(दै.भा., 14.07.20)*

कोरोना से ज्यादा सड़क हादसों में मौत

जयपुर जिले में कोरोना और सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की तुलना की जाए तो सड़क हादसों में अधिक जान गई है। जिले में अप्रेल से जुलाई तक कोरोना से 169 लोगों की जान गई। वहीं इसी अवधि में सड़क दुर्घटना से 204 लोग मौत के शिकार बने हैं।

कोविड-19 ने लोगों की जिंदगी पर असर डाला, मगर लापरवाह वाहन चालक फिर भी नहीं सुधर रहे। वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो एक दिन में दो लोग सड़क दुर्घटना के शिकार हो रहे हैं। कमिश्नरेट क्षेत्र में इस वर्ष जुलाई तक 317 लोगों की सड़क हादसों में मौत हो चुकी है। जयपुर जिले में यह आंकड़ा 500 से अधिक का है। *(रा.प., 13.08.20)*

सड़कों की गुणवत्ता की होगी जांच

प्रदेश में राज्य सरकार की तरफ से बनाई जाने वाली सड़कों की गुणवत्ता की जांच के लिए थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन शुरू किया जाएगा। वहीं सड़क बनाने वाले ठेकेदारों को 5 सालों तक उस सड़क के रखरखाव की जिम्मेदारी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह निर्देश पीडब्लूडी विभाग की समीक्षा बैठक में जारी किए हैं।

गहलोत ने कहा कि कई बार जनप्रतिनिधि गांवों को जोड़ने वाली सड़क की मांग करते हैं, ऐसे में उनकी मांग तथा क्षेत्र विशेष की जरूरत के मुताबिक ग्रामीण विकास पथ अथवा मिसिंग लिंक का कार्य कराया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अच्छी व गुणवत्तापूर्ण सड़कें बनें यह राज्य सरकार की प्राथमिकता है।

(दै.भा., 22.09.20)

लॉकडाउन में सड़क हादसों पर ब्रेक

देश में इस साल शुरुआती छह महीने में सड़क हादसों में 35 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। जनवरी से जून के बीच 1.6 लाख सड़क दुर्घटनाएं हुईं, जो पिछले छह साल के औसत से 35 प्रतिशत कम है। इस दौरान हादसे में मरने वाले लोगों की संख्या में भी 30 फीसदी की कमी आई है।

संसद में सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से 2019 में, जनवरी से जून महीने तक औसतन 2.48 लाख सड़क हादसे हुए थे। तीन छोटे पूर्वोत्तर राज्यों मेघालय, सिक्किम और नागालैंड को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। *(दै.भा., 21.09.20)*

उपभोक्ता फैसले

राज्य आयोग व राष्ट्रीय आयोग ने भी माना कागज बैग के पैसे वसूलना गलत

जयपुर निवासी महेश पारीक ने 16 अप्रैल 2016 को 399 रुपए में सोढ़ाला स्थित बाटा कंपनी के शोरूम से बाटा के जूते खरीदे थे। बाटा कंपनी की ओर से कीमत में कागज के बैग के दो रुपए अतिरिक्त जोड़कर उनसे पैसे वसूले गए। जबकि बैग पर विज्ञापन के मकसद से बाटा कंपनी का नाम और लोगो छपा था। उन्होंने कंपनी द्वारा बैग के पैसे वसूलने को गलत ठहराते हुए अपने अधिवक्ता के जरिए जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच (क्रम–4) में बाटा इंडिया लि. कंपनी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया था।

उपभोक्ता मंच ने माना कि कंपनी ने शुद्ध रूप से अपने विज्ञापन के लिए परिवादी को यह बैग दिया और बदले में उसकी कीमत भी वसूली। मंच ने बाटा कंपनी को आदेश दिया कि वह परिवादी को 10 हजार रुपए बतौर हर्जाना एवं परिवाद खर्च के रूप में अदा करे। हर्जाना राशि दो माह में अदा नहीं करने पर इस पर नौ फीसदी की दर से ब्याज भी दिया जाए।

बाटा कंपनी ने मंच के फैसले के खिलाफ पहले राज्य आयोग और बाद में राष्ट्रीय आयोग में अपील दर्ज कराई। राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आयोग ने अपील को खारिज कर दिया और उपभोक्ता मंच के फैसले को सही ठहराते हुए बाटा कंपनी को उसकी पालना करने के आदेश दिए हैं। *(रा.प., 04.08.20)*

डाक विभाग ने नहीं पहुंचाया शादी का निमंत्रण, भरना होगा जुर्माना

बीकानेर जिला उपभोक्ता आयोग में जितेन्द्र चौपड़ा ने डाक विभाग के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में उन्होंने बताया कि 20 जनवरी 2019 को उनकी शादी थी। इससे 15 दिन पहले उसने रजिस्टर्ड डाक द्वारा 84 रुपए खर्च कर किशनगंज (बिहार) निवासी रिश्तेदार हंसराज पुगलिया को डाक विभाग के जरिए निमंत्रण पत्र भेजा था। विभाग से निमंत्रण पत्र गुम हो गया। ऐसे में निमंत्रण पत्र नहीं मिलने से संबंधित रिश्तेदार शादी में नहीं पहुंच सके। जबकि शादी के 10 दिन बाद 30 जनवरी को डाक विभाग ने उन्हें सूचना दी कि संबंधित पते पर डाक भेज दी गई है। उधर, उन्हें रिश्तेदारों से पता चला कि उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं मिला। निमंत्रण पत्र नहीं मिलने से उनकी शादी में नजदीकी रिश्तेदार नहीं पहुंचे, इससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता आयोग ने रजिस्टर्ड डाक से भेजे गए निमंत्रण पत्र के खो जाने और इससे परिवादी द्वारा भेजा गया शादी का निमंत्रण पत्र निर्धारित पते पर उनके रिश्तेदारों तक नहीं पहुंचाने को विभाग का गंभीर सेवा दोष माना। आयोग ने डाक विभाग को निर्देश दिया कि वह जितेन्द्र चौपड़ा को हुए मानसिक संताप के एवज में 10,000 हजार रुपए और परिवाद खर्च के 5,000 रुपए अदा करे। *(रा.प., 30.09.20)*

देशभर में लागू हुआ उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019

उपभोक्ता संरक्षण कानून 2019 देशभर में लागू हो गया है। उपभोक्ता संरक्षण कानून 1986 में संशोधन के बाद यह कानून लाया गया है। नए कानून में उपभोक्ता को अधिक सशक्त बनाया गया है। ई–कॉमर्स कंपनियों और झूठे विज्ञापन को लेकर सख्ती बरती गई है।

उपभोक्ताओं को न केवल किसी भी शहर या जिले में शिकायत करने का अधिकार दिया गया है बल्कि वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी सुनवाई में शामिल हो सकेंगे। हालांकि इसके लिए जिला आयोग की अनुमति लेनी होगी। अब जिला आयोग एक करोड़ तक, राज्य आयोग एक से 10 करोड़ तक और राष्ट्रीय आयोग 10 करोड़ रुपए से अधिक के मामले सुन सकेगा। मामलों को मध्यस्थता के जरिए निपटाने के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। कोई झूठी शिकायत करता है तो अब 10 हजार रुपए की जगह 50 हजार रुपए जुर्माना लगेगा।

उपभोक्ता फोरम के फैसले की पालना नहीं करने पर अब दोषी को तीन साल की जेल या 25 हजार से एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऑनलाइन व्यापार में उपभोक्ता हितों की अनदेखी कंपनियों को भारी पड़ सकती है। कोई भी व्यक्ति सामान खरीदने से पहले भी गुणवत्ता को लेकर केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में शिकायत कर सकता है। प्राधिकरण को शिकायत की जांच करने और आर्थिक दंड लगाने का अधिकार है। जिला आयोग के निर्णय के खिलाफ राज्य आयोग में अपील पहले 30 दिन में होती थी जिसे अब 45 दिन कर दिया गया है। *(रा.प., 19.07.20)*

कोरोना से बचाव का रखें पूरा ध्यान

प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसकी रोकथाम के लिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह मास्क पहनकर ही बाहर निकलें।

आदेशों के अनुसार मिलते समय दो गज की दूरी बनाएं रखें। सार्वजनिक स्थान पर नहीं थूंके तथा भीड़भाड़ में जाने से बचें। मिलते समय हाथ मिलाने या गले लगने जैसे अभिवादन से बचा जाए। बार–बार साबुन व पानी से या सेनेटाइजर से हाथों को धोएं। कार्यस्थलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की जाए।

शादी समारोह या अंतिम संस्कार में निर्धारित संख्या में ही लोग शामिल हों। दुकानों व सार्वजनिक स्थानों पर बार–बार छूने वाली सतहों की सफाई व हैंड वॉश का पालन करें।

स्त्रोतः रा.प.: राजस्थान पत्रिका, दै.भा.: दैनिक भास्कर, न.नु.: नफा नुकसान, दै.न.: दैनिक नवज्योति, स.ज.: समाचार जगत, रा.दू.: राष्ट्रदूत

पाँचवा–स्तम्भ (समाचार पत्रिका) प्रकाशक कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, डी–217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016, फोनः 91.141.513 3259
फैक्सः 228 2485, टेलीफैक्सः 401 5395, ई–मेलः cart@cuts.org, वेबसाईटः www.cuts-international.org
यहां भी दिल्ली, कोलकता और चित्तौड़गढ़ (भारत); लुसाका (जाम्बिया); नैराबी (केन्या); आक्करा (घाना); हनोई (वियतनाम); जिनेवा (स्विटजरलैंड) और वॉशिंगटन डी.सी. (यूएसए)